कृषि राजनीति एवं अर्थनीति

सुधांशु के के मिश्रा

सारांश

- हिन्दुस्तान गावों में बसा है लेकिन उत्पादक रोजगार एवं आय अर्जन के अवसर कृषि क्षेत्र के बाहर निकल रहे हैं।
- पिछले 6 वर्षों में कृषि विकास दर एक पेंडुलम की तरह (-) 7.21% (वर्ष 2002-03) से लेकर 10.00% (वर्ष 2003-04) तक deviate कर रही है।
- भारत सरकार फार्म क्रेडिट पैकेज के अन्र्तगत अगले 3 वर्षों (2003-04 से 2006-07 तक) में कृषि क्षेत्र में साख वित्त प्रवाह को दुगना करने के कार्यक्रम के परिणाम।
- एन एस एस के 48वे चक्र में land and livestock holding सर्वे में गरीबों का प्रोफाइल।
- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के परिणाम।
- कृषि क्षेत्र में लगे लोगों को उचित आय एवं वर्ष भर पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह।
- राज्य कृषि क्षेत्र नीति के ध्येय ।

15 अगस्त 1947 को आजाद भारत देश के समय हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने महात्मा गांधी के निम्न शब्दों को राज्य नीति के ध्येय के रुप में रखा था "प्रत्येक दुखी के आंख के आंसू पोछे जायें" ।

यदि एक राजनैतिक रुप मे कृषि क्षेत्र को देखा जाये तो वे कृषि क्षेत्र से निम्न दो अपेक्षाएं करते हैः

(1) कृषि क्षेत्र की समस्त जनसंख्या को प्रचुर एवं सस्ते खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नियमित रुप से कर पाने की क्षमता।

(2) कृषि क्षेत्र में लगे लोगों को उचित आय एवं वर्ष भर पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाने की क्षमता।

जहां तक पहली अपेक्षा का संबंध है, हरित एवं श्वेत क्रान्ति के प्रभाव से भारतीय कृषि व्यवस्था प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न, दूध, फल सब्जियों आदि का उत्पादन कर पाने में सक्षम रही है।

कृषि क्षेत्र मे लगे लोगों को उचित आय एवं वर्ष भर पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा पाने के संबंध मे कई विफलतायें दिखी हैं। कृषि उत्पादन में प्रत्येक वर्ष के उत्पादन में भारी उतार चढाव देखने को मिले हैं। वर्षा आधारित एवं अत्यंत कम वर्षा क्षेत्रों में (Rainfed arid and semi arid areas) में अब भी किसान अत्यंत गरीबी में जीवन जी रहे हैं। हजारों किसान पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं जो कि निम्न कारणों की तरफ इशारा करते हैंः-

(1) हरित क्रान्ति में लाये गये तकनीकी विकास शायद पिछड़े वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों एवं उन्नत कृषि क्षेत्रों मे छोटे एवं मझोले किसानों तथा बटाईदार किसानों तक नहीं पहुंच सके हैं।

(2) अब भी किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश मे किसान कपास, मिर्च एवं आलू की फसलों में लगातार दुख उठाता है एवं कई बार किसान को मिलने वाली फसल की कीमत फसल लागतों को पूरा करने लायक भी नहीं होती है।

3. यदि हम कुल विकास दर में कृषि के योगदान को देंखें तो पायेंगे कि

टेबल 1 - कुल विकास दर में कृषि का योगदान

वर्ष	विकास दर	कृषि विकास दर
2000-2001	4.4%	(-) 0.2%
2002-2003	3.8%	(-) 7.2%
2004-2005	7.5%	+0.00%
2006-2007	9.2%	+2.7%

स्त्रोतः सीएसओ

देश तो तरक्की कर रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र बीमार है। हिन्दुस्तान गावों में बसा है लेकिन उत्पादक रोजगार एवं आय अर्जन के अवसर कृषि क्षेत्र सें बाहर निकल रहे हैं। इस का सीधा मतलब हुआ कि आज खाली कृषि पर निर्भर रह कर जीवन यापन कर पाना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है।

4. सकल घरेलू उत्पाद में कृषि विकास दर

टेबल -2 - सकल घरेलू उत्पाद मेंकृषि विकास दर (1999-2000 की कीमतें)

	वर्ष						
	2000-01	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**
कृषि विकास दर	0.21%	6.3%	(-)7.21%	10.00%	0.00	6.00%	2.7%

स्त्रोत : Economic Survey 2007

यदि हम पिछले 5 वर्षों की कृषि क्षेत्र विकास दर को देखें तो पायेंगे कि Sensex की तरह पिछली 6 वर्षों में कृषि विकास दर एक पेंडुलम की तरह (-)7.21% (वर्ष 2002-03) से लेकर 10.00% (वर्ष 2003-04) तक deviate कर रही है।

इसी बात को हम आगे देखें तो पायेंगे कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन वर्ष 1999-2000 में किया गया (76.4 मी टन) और तब से 10 वर्षों में हम इस स्तर को नहीं छू पाये हैं। दलहन उत्पादन में भी इसी तरह वर्ष 1998-99 के उत्पादन स्तर को हम दस वर्षों में केवल एक बार वर्ष 2003-04 में छू सके हैं।

5. ये सभी तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि

- कृषि कार्य अब भी उतना ही जोखिम भरा है जितना आज से पचास वर्ष पहले था।
- यदि आज भी कृषि वर्षापर आधारित है तो पिछले पचास वर्षों में सरकार द्वारा सिंचाई कृषि विस्तार, रसायनिक खाद्य उत्पादन आदि में किये गये निवेश की प्रभाविकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है ।

6.	भारत सरकार ने 2004 में फार्म क्रेडिट पैकेज के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में कृषि क्षेत्र में साख वित्त प्रवाह को दुगना करने का कार्यक्रम चलाया। इसके परिणाम स्वरुप सीधा कृषि ऋण (direct agricultural advance) जो कि वर्ष 2003-04 में रु.86,980 करोड़ थे वर्ष 2005-06 में रु.1,80,486 करोड़ हो गये। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा सभी पात्र किसानों (भूमिहीन बटाईदार किसानों को शामिल कर के) को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने का एक सघन कार्यक्रम चलाया गया जो कि एक सराहनीय कदम है। इस पूरे कार्यक्रम की नियमित रुप से नाबार्ड द्वारा समीक्षा की गई। इसी कड़ी के अर्न्तगत नाबार्ड द्वारा सभी सहकारी बैको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को बटाईदार किसानों (Share cropper), मौखिक पट्‌टाधारक किसानों एवं पुराने चूककर्ताओं को भी शामिल करने के लिये भी निर्देशित किया गया जो कि एक सराहनीय कदम है।

7.	एन एस एस के 48वे चक्र में land and livestock holding सर्वे में गरीबों का प्रोफाइल देखते हुए यह पाया गया कि कृषि में विकसित क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा आदि में कृषि मजदूर गरीबों में जीविका वार प्रमुख हिस्सा बनते हैं। यदि हम वर्षा अधारित एवं शुष्क कृषि क्षेत्रों को देखें तो लघु एवं सीमान्त कृषक भी गरीबों मे आ जाते हैं। इन क्षेत्रों में आय अर्जक रोजगार के अवसर न उपलब्ध हो पाने के कारण वे विकसित क्षेत्र में कृषि मजदूरी के लिए भारी तादाद में जाते हैं। यदि वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में हम लोग फार्म उत्पादकता को बढ़ा सके तो विकास अत्यंत तीव्र जो जायेगा।

8.	वर्तमान मे कृषि क्षेत्र की कमजोरियों को देखते समय हमको पुराने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के परिणामों को भी देखने की अत्यंत आवश्यकता है ।

टेबल 3

एकीकत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) वर्ष 1990-91 से वर्ष 1998-99 के परिणाम

कुल परिवार	कुल बैक ऋण	कुल निवेश
5.40 करोड़ गरीब परिवार	रु 22,542 करोड़	रु 33,953 करोड़

उक्त कार्यक्रम के वर्ष 1998-99 मे प्लॉनिंग कमीशन द्वारा किये गये Concurrent evaluation में निम्न तथ्य सामने आये।

(1) औसतन 14.8 प्रतिशत लाभार्थी ही गरीब रेखा को पार कर पाये। इस का मतलब करीब करीब 4.80 करोड़ परिवार गरीबी से बाहर नही निकल पाये एवं संभवतः अब भी अशिक्षा बेरोजगारी एवं अपर्याप्त आय के शिकार हैं।

(2) IRDP कार्यक्रम मे दिये गये बैक ऋणो मे औसत वसूली 41% रही। इसका मतलब ये हुआ कि 3.48 करोड़ परिवार बैक लोन चुका पाने मे अक्षम रहे हैं, तथा वर्तमान मे चूककर्ता होने की वजह से बैक ऋण तथा अन्य सरकारी योजनाओं में चयन के लिए अपात्र है। यदि औसत एक परिवार में 5 सदस्यों की संख्या को लें तो करीब करीब 20 करोड़ ग्रामीण गरीब सरकारी योजनाओं एवं बैंक ऋणों से वंचित है। यही वो क्षेत्र है जो कि मुख्यतः कृषि मे लगे मजदूर, सीमान्त कृषक एवं गरीब कुटीर उद्योग धन्धों मे लगे स्वरोजगारियों का है तथा कृषि क्षेत्र के उतार चढाव को प्रमुखता से भोगता है। जब तक इन 20 करोड़ गरीब परिवारों को चिन्हित करके उन्हे दुबारा मुख्य धारा में लाने की नीतियां नही बनाई जायेंगीं तब तक कृषि क्षेत्र बीमार ही रहेगा।

(उक्त लेख मे दिये गये विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं)